भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 252

30 नवम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

सहकारिता संबंधी केंद्रीय डेटाबेस

252. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया:
श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की मंशा सहकारिता संबंधी केंद्रीय डेटाबेस विकसित करने की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार करने के पीछे का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों और सहकारिता संगठनों से परामर्श किया है या करने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

<u>सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)</u>

सहकारिता मंत्री (SHRI AMIT SHAH)

(क): जी हाँ।

(ख): सहकारी समितियों की संख्या, उनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ, उनका स्थान, उनकी वित्तीय स्थिति, भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका योगदान आदि की जानकारी, सहकारी क्षेत्र में कोई नीतिगत पहल करने या कोई कल्याणकारी योजना तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण अव्यव हैं। राष्ट्रीय डेटाबेस, नव-निर्मित सहकारिता मंत्रालय के लिए व्यवसाय के अधिदेशित कार्य आवंटन की पूर्ति हेतु अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में एक ऐसा कदम प्रदान करेगा।

(ग) और (घ): जी हां, राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करना किसी भी नीति के निर्धारण का एक अभिन्न अंग है।

*****